

मानकीकरण, प्रमाणन और बाजार निगरानी में नई पहल पर जर्मनी और भारत की भागीदारी

भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स एण्ड एनर्जी के नेतृत्व में गुणतापरक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भारत-जर्मन कार्य समूह की 5वीं वार्षिक दो दिवसीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। यह कार्य समूह 2013 से हर वर्ष बैठक कर व्यापार के लिए तकनीकी चुनौतियों की पहचान करता है, तथा बढ़ते हुए डिजिटल व्यवसाय के परिवेश में भारत एवं जर्मनी के बीच व्यवसाय के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में समाधान निकालता है।

उपभोक्ता मामले सचिव श्री अविनाश के. श्रीवास्तव ने बताया कि जर्मनी एक महत्वपूर्ण भागीदार है, और द्विपक्षीय वार्तालाप से आपसी समझ एवं विश्वास गहरा होता है, तथा भारत एवं जर्मनी के उद्योगों के साथ-साथ हम उपभोक्ताओं के प्रासंगिक मुद्दों पर कार्य करने में सक्षम होते हैं। यह कार्य समूह भारत सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप है। श्री श्रीवास्तव जी ने प्रकाश डाला कि यह अत्यधिक प्रासंगिक विषयों पर कार्य करता है, दोनों देशों से विशेषज्ञों को साथ लाता है, और ये विशेषज्ञ भारत में बाजार निगरानी पद्धति को सशक्त बनाने पर अवधारणाएँ विकसित करते हैं।

डिजिटल एंड इन्वोवेशन पॉलिसी एट जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स एण्ड एनर्जी के महानिदेशक, एवं जर्मन प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता कर रहे श्री स्टीफन स्नोर ने बल दिया कि कार्यकारी समूह से सहयोग जर्मनी और भारत के आर्थिक संबंधों की मजबूती की ओर संकेत करता है और एक दूसरे से सीखने की इच्छा को दर्शाता है। द्विपक्षीय सहयोग से व्यापार और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। श्री स्नोर ने कहा कि जर्मन प्रतिनिधिमंडल यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ है कि भारतीय भागीदारों ने सुव्यवस्थित जर्मन मॉडल की सराहना की है।

पहली बार, वाणिज्य विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय जैसे सरकारी विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के 50 से अधिक जर्मन तथा भारतीय स्टैकहोल्डरों, उद्योग संघ (एफआईसीसीआई, सीआईआई, वीडिएमए, वीडिए), मानकीकरण एवं प्रत्यायन निकाय, जिनमें भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) तथा जर्मन स्टैंडरडाइजेशन इन्स्टिट्यूट (डीआईएन,डीकेई) तथा भारत जर्मन चैम्बर्स ऑफ कामर्स (आईजीसीसी) ने भाग लिया । सहभागियों ने सहयोग के उन क्षेत्रों पर सहमति व्यक्त की, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप द्विपक्षीय व्यापार और व्यवसाय को सुगम बनाया जा सकता है, और अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है, उदाहरण के लिए परीक्षण परिणामों को परस्पर मान्यता देना शामिल है। नई कार्य योजना में मशीनरी सुरक्षा, मोटर वाहन उद्योग, इलेक्ट्रो मोबिलिटी चार्जिंग के बुनियादी ढांचे, उद्योग 4. 0(आईओटी) और डेटा संरक्षण शामिल है।



Bureau of Indian Standards

भारतीय मानक ब्यूरो

Press Release

INDO-GERMAN WORKING GROUP ON QUALITY INFRASTRUCTURE

15-16 January, 2018

New Delhi, India

Germany and India Partner on new initiatives in Standardisation, Certification and Market Surveillance

**Indo-German Working Group on Quality Infrastructure marks five years of
Cooperation in New Delhi**

The 5th Annual Meeting of the Indo-German Working Group on Quality Infrastructure, led by the Indian Ministry for Consumer Affairs, Food and Public Distribution and the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy was held on January 15 and 16, 2018 in New Delhi. The Working Group meets annually since 2013, and identifies technical challenges to trade, and seeks solutions to increase business opportunities between India and Germany in an increasingly digitised business environment.

Secretary Consumer Affairs Mr. Avinash K. Srivastava said Germany is as an important partner, and that the bilateral dialogue deepens mutual understanding and trust, and enables to work on issues that are relevant for the Indian and German industry as well as consumers. The Working Group is well aligned with the priorities of the Indian Government. It works on highly relevant topics, and brings together experts from both countries, who for instance develop ideas on how to strengthen the market surveillance system in India and protect consumers better, Mr. Srivastava highlighted.

Mr. Stefan Schnorr, Director General for Digital and Innovation Policy at the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, who headed the German delegation, emphasised that cooperation in the Working Group is a sign of Germany's and India's strong economic

relations, and shows the willingness to learn from each other. The closer the partnership becomes, the more relevant it would be to find solutions that ease doing business. Business and consumers would benefit from the bilateral cooperation. Mr. Schnorr added that the German delegation is delighted to see that the Indian partners appreciate the well-established German model, where the industry is in the driver's seat steering towards a more digitalised world, and developing and harmonising standards accordingly.

For the first time, government officials from other line ministries including DoC, MeitY, MoRTH, and DHI joined over 50 German and Indian stakeholders from the private sector, including industry associations (FICCI, CII, VDMA, VDA), standardisation and accreditation bodies, among them the Bureau of Indian Standards (BIS) and German standardisation institutes (DIN, DKE), as well as the Indo German Chamber of Commerce (IGCC). The participants agreed on cooperation areas where bilateral trade and business can be facilitated by aligning to international standards, and easing conformity assessment procedures, for instance through mutual recognition of test results. The new Work Plan includes collaboration in machinery safety, automotive industry, electro mobility charging infrastructure, Industry 4.0 (IoT), and data protection.